

135
11/10

क्रमांक- 90 वि. 1 - 29/97-3439 पटना, दिनांक 15.7.97

प्रो. पी.एस. नारायणन,
सरकार के सचिव।

78
10

उपायुक्त,
रांची।

विषय: उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी जिला उपभोक्ता फोरम विद्या
में तृतीय / इतुर्ध्वर्गीय कर्मचारियों के समाखोज के आधार पर नियुक्ति।

प्रसंग: आपका फांक- 351/11 दिनांक 15.7.97 एवं फांक- 300 दिनांक 5.7.
महाभाग,

निर्देशानुसार, उपर्युक्त विज्ञापक एवं प्रसंग में दिनांक 16/9/97 को माननीय
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय जिला पदाधिकारी / उपायुक्त की बैठक के
आपके हुई वाक्ता का स्मरण किया जाय। आपने अस्तुथा किया है कि राज्य सरकार
द्वारा उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत योजना मद में सृजित पदों पर रांची जिल
फोरम में नियुक्ति किये जानेवाले कर्मियों के पदनाम के संबंध में स्थिति स्पष्ट किया

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने भारत सरकार के अनुसूचा
के आलोक में अधिगत भारतीय आकार को ध्यान में रखाकर सभी जिला उपभोक्ता प
में आपूर्ति विभाग के अन्तर्गत समान स्तर से अन्य पदों के अलावा निजी सहायक / आभु
जैव कर्ल एवं निम्नवर्गीय लिपिक का पद सृजित किया है। इन पदों के वेतनमान के अस्तु
निजी सहायक का जो पद है वह आभुलिपिक का ही है तथा जैव कर्ल एवं निम्नवर्गी
लिपिक का जो पद है वह भी लिपिक का है। कर्मचारियों की दरियता, वेतन एवं अ
कीठनाईयों का निराकरण जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी द्वारा किया जाना है
अतएव इन पदों पर जिला पदाधिकारी का प्रशासनिक नियंत्रण रहना आवश्यक है
इसलिए जिला पदाधिकारी को नियुक्ति पदाधिकारी बनाया गया है। चूंकि उन प
पर आपका प्रशासनिक नियंत्रण है, इसलिए आप अपनी सुविधानुसार निजी सहाय
जैव कर्ल एवं निम्नवर्गीय लिपिक को जिला संघ के अन्य शाखा में क्रमशः आभुलि
एवं लिपिक के रूप में स्थानान्तरित कर ^{कार्य} ले सकते हैं, परन्तु उनके स्थान पर जो आभु
एवं लिपिक उपभोक्ता संरक्षण शाखा में यदि स्थानान्तरित होकर आये तो उ
पद पर बने रहने की अवीधा में वे निजी सहायक / जैव कर्ल एवं निम्नवर्गीय लिपिक है
से पदनामित होंगे।

136

: 2 :

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में औपचारिक रूप से कार्मिकों के योगदान की तिथि से ही निम्नलिखित-प्रश्न निर्गत करने की कृपा की जाय।

कि.वा.स.भा.जल,

~~सरकार के सचिव।~~

20/9/94

ज्ञापक- प्र 9. वि 1 - 29/97- 3437 पृष्ठा, दिनांक 20.9.94

प्रतिबंधित रूप से जिला पदाधिकारी / उपायुक्त को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

~~सरकार के सचिव।~~

20/9/94